राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 9086/2019

भंवरलाल पुत्र श्री श्रीनारायण, निवासी गांव महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मेसर्स लैंड मार्क एग्जीक्यूटिव प्रा. लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 3, मुनिरिका मार्ग, नई दिल्ली अधिकृत एजेंट प्रदीप शर्मा पुत्र नरेश चंद शर्मा, निवासी एफ-1, विजय पथ, बनीपार्क, जयपुर के माध्यम से।

2. गोपाल पुत्र लादुराम, निवासी ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला कांगनाड़, जयपुर।

3. श्रीमती कृष्णा देवी, पुत्री श्रीनारायण शर्मा निवासी, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला सांगानेर, जयपुर। वर्तमान में निवासी ए- 48, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पनीपेच, जयपुर।

(मृतक के बाद से)

3/1. जीतेन्द्र पुत्र स्व. नारायण सहाय निवासी ए-48, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

3/2. चन्द्र मोहन पुत्र स्व. नारायण सहाय, निवासी ए-48, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

3/3. शेखर पुत्र स्व. नारायण सहाय, निवासी ए-48, शिवाजी मार्ग, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर।

3/4. रामा देवी पुत्री नारायण सहाय पत्नी अमित शर्मा, पथ-7, बंधु नगर, मुरलीपुरा, जयपुर।

3/5. श्यामा देवी निवासी नारायण सहाय पत्नी निखिल शर्मा, निवासी गांव झंनी, पोस्ट बार के बालाजी, जयपुर।

4. तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर के माध्यम से राजस्थान सरकार।

5. राजस्व बोर्ड, राजस्थान अजमेर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

6. राजस्व अपीलीय प्राधिकरण, जयपुर।

7. सहायक जिलाधीश सह कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर सिटी- I, जयपुर।

8. श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय श्रीनारायण शर्मा की पत्नी, (हटाए गए प्रत्यर्थी)।

----प्रत्यर्थीगण

---

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री एन.के. मालू, श्री प्रत्यूष शर्मा

वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री एम एम रंजन, सीनियर अधिवक्ता श्री रोहन अग्रवाल के साथ।

श्री आर.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अधिराज मोदी के साथ।

---

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गौड़

<u>आदेश</u>

<u>06/07/2022</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य :</u>

वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है::

(i) राजस्व बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अपास्त करते हुए दिनांक 9 अप्रैल, 2019 का आदेश;

(ii) राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी 2016;

(iii) सहायक जिलाधीश एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-प्रथम, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जून, 2015;

(iv) सहायक जिलाधीश और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-I, जयपुर द्वारा पारित निर्णय और प्रारंभिक डिक्री दिनांक 02 जून, 2015;

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी-प्रत्यर्थी-मैसर्स लैंड मार्क एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसीएम, जयपुर सिटी-I, जयपुर की अदालत में विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और प्रारंभिक डिक्री 02 जून, 2015 को पारित की गई थी और न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1-गोपाल पुत्र लाडूराम, प्रत्यर्थी संख्या 3-भंवर लाल पुत्र श्रीनारायण (रिट याचिका में याचिकाकर्ता) और प्रत्यर्थी संख्या 4–श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्रीनारायण ने लिखित बयान दायर किए थे, जिससे वे संपत्ति के विभाजन के लिए भी सहमत हुए और आगे, प्रत्यर्थी संख्या 2–श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्रीनारायण उपस्थित नहीं हुईं और उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही शुरू कर दी गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक डिक्री पारित करते समय, निचली अदालत ने संपत्ति के विभाजन का आदेश पारित किया, जिसकी कुल माप 10.800 हेक्टेयर थी और तहसीदार सांगानेर को मेट्स और सीमा के आधार पर विभाजन नियमों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था और पक्षकारों द्वारा संपत्ति के कब्जे पर विचार करने के लिए, तहसीलदार सांगानेर को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि प्रारंभिक डिक्री पारित करते समय आदेश पत्र में यह दर्ज किया गया था कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट 15 जून 2015 को न्यायालय के समक्ष रखी जानी थी।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों

को कोई नोटिस जारी किए बिना, तहसीलदार सांगानेर ने 11 जून, 2015 को एक रिपोर्ट तैयार की और इसमें कृष्णा देवी बनाम भंवर लाल 09 अगस्त, 2004 से एसडीओ, जयपुर-II के रूप में लंबित एक मुकदमे के लंबित होने का भी उल्लेख किया और इसे एसीएम, जयपुर शहर-I, जयपुर में स्थानांतरित किया जा रहा था, जहां 17 अगस्त, 2004 को कब्जे और रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि निचली अदालतने 11 जून, 2015 को तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार डिक्री पारित करने के लिए मामले की सुनवाई की और मामले को राजस्व लोक अदालत/कैंप कोर्ट में 12 जून, 2015 के लिए तय किया गया था।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि 11 जून, 2015 को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था और 12 जून, 2015 को, याचिकाकर्ता राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं था और उसे अग्रिम भुगतान के लिए 12 जून, 2015 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित होने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि 12 जून 2015 को एक आदेश-पत्र जारी किया कि संपत्ति के बंटवारे की आपत्ति के बारे में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और पक्षों की ओर से अधिवक्ता मौजूद थे और इस प्रकार, संपत्ति के बंटवारे पर आपत्ति के अनुसार, जैसा कि तहसीलदार द्वारा निर्णय लिया गया, अलग-अलग निर्णय और डिक्री पारित की गई।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में अनुरोध किया है कि निचली अदालत ने 12 जून, 2015 के आदेश के तहत निर्णय और डिक्री पारित की और कुछ खसरे वादी-प्रत्यर्थी - मेसर्स लैंड मार्क एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड और के विधिक उत्तराधिकारियों को आवंटित किए गए थे। स्वर्गीय श्रीनारायण पुत्र लादूराम और इस प्रकार, श्रीनारायण के स्थान पर, श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्रीनारायण, भंवर लाल पुत्र श्रीनारायण (रिट याचिका में याचिकाकर्ता) और श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्रीनारायण, जो श्रीनारायण के विधिक प्रतिनिधि थे, को कुल

4.0320 हेक्टेयर भूमि के पांच खसरे आवंटित किए गए थे और इसके अलावा, गोपाल पुत्र लादु राम को भी पांच खसरों में कुल 2.0160 हेक्टेयर भूमि का पात्र माना गया था।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि निर्णय के अंत में एक नोट भी लगाया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि एक मुकदमा लंबित था, जिसे एसीएम, जयपुर शहर-I, जयपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था और इस तरह, 17 तारीख के आदेश के तहत अगस्त, 2004 में कृष्णा देवी द्वारा दायर एक मामले में अंतरिम आदेश भंवर लाल के खिलाफ जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने 12 जून, 2015 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की और प्रत्यर्थी संख्या 3 - कृष्णा देवी ने भी प्रारंभिक के खिलाफ एक अलग अपील दायर की। साथ ही अंतिम डिक्री क्रमशः दिनांक 02 जून, 2015 और 12 जून, 2015 को हुई।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने 01 फरवरी, 2016 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 - कृष्णा देवी द्वारा दायर दोनों अपीलों को अपास्त कर दिया और 12 जून 2015 के निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2016 के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा राजस्व बोर्ड और राजस्व बोर्ड के समक्ष इसे चुनौती दी जिसे याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को पोषणीय न पाते हुए अपास्त कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में दलील दी है कि राजस्व बोर्ड ने 12 जून, 2015 के अपने निर्णय में कहा है कि निचली अदालतने तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के संदर्भ में राजस्व लोक अदालत में अंतिम डिक्री पारित कर दी है और जैसाकि सहमति व्यक्त की गई है। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता, जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ

में अंतिम डिक्री पारित करने की सहमति थी, उस पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, लेकिन उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और चूंकि न्यायिक कार्यवाही में बहुत पवित्रता होती है और कोई आरोप नहीं होता है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एनके मालू ने विद्वान अधिवक्ता श्री प्रत्यूष शर्मा की सहायता से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

(i) 12 जून 2015 का आक्षेपित निर्णय और डिक्री कानून की नजर में अमान्य है, क्योंकि इसे मिलीभगत से पारित किया गया है।

(ii) 12 जून, 2015 का निर्णय और डिक्री याचिकाकर्ता को तारीख आगे बढ़ाकर मामले पर निर्णय लेने के लिए किसी भी नोटिस के अभाव में पारित किया गया था।

(iii) लोक अदालत में पारित निर्णय और डिक्री पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं और समझौते पर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी हस्ताक्षर के अभाव में, लोक अदालत द्वारा पारित डिक्री अमान्य है।

(iv) 15 से 11 जून, 2015 तक सुनवाई को पहले करना और फिर याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में 12 जून, 2015 को आदेश पारित करना सबसे असामान्य तरीका है, क्योंकि पक्षकारों के अधिवक्ता की कथित उपस्थिति में तारीख को पहले करके मुकदमे का निर्णय किया गया था।

(v) अंतिम डिक्री दिनांक 12 जून, 2015 को तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 11 जून, 2015 के आधार पर पारित की का गई थी और उक्त रिपोर्ट में साइट के साथ-साथ मुकदमे की संपत्ति के रिकॉर्ड के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में अंतरिम आदेश के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। इस प्रकार, श्रीमती कृष्णा देवी और भंवरलाल (रिट याचिका में याचिकाकर्ता) के बीच लंबित सिविल मुकदमे के मद्देनजर कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी।

(vi) न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के मद्देनजर आपत्तियों पर विचार किया जाना

था, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किए बिना, आवश्यक पक्ष की अनुपस्थिति में और याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार किए बिना, स्वयं और ऐसी रिपोर्ट तैयार की। भूमि के वास्तविक भौतिक कब्जे के संबंध में कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकी।

(vii) निचली अदालत यह विचार करने में विफल रही कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और राजस्थान किरायेदारी (राजस्व बोर्ड) नियम, 1955 (संक्षेप में "1955 के नियम") के नियम 18 से 21 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और धोखाधड़ी की गई थी याचिकाकर्ता और अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा और इस तरह, कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी।

(viii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 (संक्षेप में "2009 के विनियम") में प्रदान की गई प्रक्रिया का लोक अदालत के रूप में घोर उल्लंघन किया गया है, जबकि पंचाट पारित करते समय पक्षकारों को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना आवश्यक है या लोक अदालत के सदस्यों के समक्ष अपने हस्ताक्षर करके पंचाट जारी करें।

(ix) वादी और अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई धोखाधड़ी निचली अदालत के समक्ष स्पष्ट थी और दोनों अपीलीय न्यायालय धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहीं।

(x) प्रत्यर्थी-श्रीमती कृष्णा देवी ने स्वयं राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील दायर की थी और अपील अपास्त होने के बाद, उक्त प्रत्यर्थी को प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के अनुपालन की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंतिम डिक्री और इस प्रकार, अपीलीय मंच द्वारा पारित निर्णय उसके लिए बाध्यकारी हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है::

(1) पंजाब सरकार और अन्य बनाम जालौर सिंह एवं अन्य [(2008) 2 एससीसी 660

(2) सेवा सिंह बनाम दैनिक लोक अदालत (पीठ संख्या 1), पंजाब और हरियाणा उच्च

न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य [सीडब्ल्यूपी संख्या 7344-2011 (ओ एंड एम), 14 अक्तूबर 2015 को निर्णय लिया गया] [एमएएनयू/एससी/0772/2022]

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता ने श्री अधिराज मोदी की सहायता से, प्रत्यर्थी संख्या 3 - श्रीमती कृष्णा देवी की ओर से उपस्थित हुए और निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी:

(i) इसमें कोई विवाद नहीं है कि वाद भूमि को वादी-प्रत्यर्थी के बीच विभाजित किया जाना है-मेसर्स लैंड मार्क एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास 2/5 वां हिस्सा है, प्रत्यर्थी संख्या 2-गोपाल के पास 1/5 वां हिस्सा है और श्रीमती कृष्णा, भंवरलाल और श्रीमती लक्ष्मी देवी के पास 2/5 हिस्सा है।

(ii) निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी ने मुकदमे में लिखित बयान दायर किया था, जहां उसने वादी के दावे को उसी अनुपात में संपत्ति/भूमि के विभाजन के लिए स्वीकार किया था, जैसाकि मुकदमे में दलील दी गई थी।

(iii) याचिकाकर्ता के पास 12 जून, 2015 को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते/निपटान को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो इस तरह के समझौते/निपटान के खिलाफ, एकमात्र उचित फोरम उसी न्यायालय से संपर्क करना था, जिसने आदेश पारित किया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी और वर्तमान रिट याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं है।

(iv) अधिवक्ता, जो किसी पक्ष/वादी की ओर से प्रस्तुत होता है, उसके पास पक्ष की ओर से हस्ताक्षर करने की पूरी क्षमता है और यदि याचिकाकर्ता का अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से समझौता/निपटारा करने के लिए उपस्थित था, तो इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया और पक्षकार-याचिकाकर्ता को अलग से नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 - श्रीमती कृष्णा देवी के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है :

i. पुष्प देवी भगत (मृत) एल आर एस के माध्यम से साधना राइ (श्रीमती) बनाम राजिंदर सिंह और अन्य [(2006) 5 एस सी सी 566

ii. आर. राजन्ना बनाम एस. आर. वेंकटस्वामी और अन्य [एयर 2015 एससी 706]

iii. कटुकंडी इकाठी कृष्णन और अन्य बनाम कटुकंडी इकाठी वल्सन वासन और अन्य [सिविल अपील संख्या. 6406- 6407/2010], 13 जून, 2022 को निर्णित।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एम. रंजन, विद्वान अधिवक्ता श्री रोहन अग्रवाल की सहायता से, प्रत्यर्थी संख्या 1 - मेसर्स लैंड मार्क एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने सही आदेश पारित किया है और प्रारंभिक डिक्री भी जारी की गई थी जिसे सभी पक्षों की स्वीकृति के आधार पर पारित किया गया याचिकाकर्ता और किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को निचली अदालतों द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक डिक्री का आदेश तहसीलदार द्वारा आपत्ति पर विचार करने के प्रभाव से था और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, तहसीलदार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और तदनुसार, अंतिम डिक्री पारित की गई।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-वादी प्रश्नाधीन भूमि का एक वास्तविक खरीदार है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तुच्छ विवाद के कारण, प्रत्यर्थी को पीड़ित नहीं किया जा सकता है और प्रत्यर्थी ने खरीदी गई भूमि के टुकड़े और यहां तक कि घरों का भी निर्माण किया गया है और केवल वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण, प्रत्यर्थी-वादी अकेले पीड़ित है और इस प्रकार, यह न्यायालय रिट याचिका को अपास्त कर सकता है।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और मामले की सावधानीपूर्वक जांच की है।

यह न्यायालय, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न दलीलों पर विचार

करने से पहले, कुछ निर्विवाद तथ्यों का वर्णन करना उचित समझता है:

(क) वादी-प्रत्यर्थी-मेसर्स लैंड मार्क एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड ने विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने अपने 2/5 वें हिस्से और प्रत्यर्थी संख्या 2-श्रीमती कृष्णा देवी, 2/5 वें हिस्से प्रत्यर्थी संख्या 3- भंवरलाल (रिट याचिका में याचिकाकर्ता), प्रत्यर्थी संख्या 4- श्रीमती लक्ष्मी देवी के कुल भूमि का 1/5 हिस्सा और प्रत्यर्थी संख्या 1 - गोपाल का दावा करते हुए संपत्ति/भूमि के विभाजन के लिए प्रार्थना की थी।

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 1 - गोपाल ने वादी-प्रत्यर्थी के दावे को स्वीकार करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया और प्रारंभिक डिक्री देने और भूमि के विभाजन और राजस्व रिकॉर्ड को सही करके मुकदमे का अंतिम निर्णय करने की भी प्रार्थना की।

(ग) प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4, अर्थात याचिकाकर्ता - भंवरलाल और श्रीमती लक्ष्मी देवी ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया और भूमि के विभाजन और प्रारंभिक डिक्री पारित करने की भी प्रार्थना की और विभाजन के बाद अलग-अलग खसरे खोले जाने और राजस्व रिकॉर्ड को तदनुसार संशोधित करने की मांग की।

(घ) 2 जून, 2015 को, प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी- श्रीमती कृष्णा देवी तामील अवधि के बावजूद उपस्थित नहीं हुईं और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

(ङ) उसी तारीख को, न्यायालय ने मुकदमे में प्रत्यर्थीगण की स्वीकारोक्ति के आधार पर, एक आदेश पारित किया और साथ ही संपत्ति के विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित की और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी (कुरेजत रिपोर्ट) और मामला बंद कर दिया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट पर विचार हेतु 15 जून 2015 की तारीख नियत की गई।

(च) मामला 11 जून, 2015 को एसीएम जयपुर शहर- I, जयपुर के समक्ष रखा गया था और वादी और प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे और आपत्तियों पर विचार करने के लिए मामले को 12 जून, 2015 को राजस्व लोक अदालत में रखने पर सहमति हुई थी (तहसीलदार की कुरेजत रिपोर्ट) और पक्षों के अधिवक्ता 12 जून, 2015 को अंतिम

निपटान करने पर सहमत हुए।

(छ) आपत्तियां (कुरेजत रिपोर्ट) दिनांक 11 जून, 2015 को तहसीलदार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कुल 10.800 हेक्टेयर भूमि को वादी-प्रत्यर्थी - गोपाल और स्वर्गीय श्रीनारायण के बीच और श्रीनारायण की मृत्यु के कारण, प्रत्यर्थी - श्रीमती कृष्णा देवी, के बीच विभाजित किया था। भंवरलाल (रिट याचिका में याचिकाकर्ता) और श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्रीनारायण को जमीन का एक निश्चित टुकड़ा आवंटित किया गया था। उक्त रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि एक मुकदमा एसडीओ कोर्ट, जयपुर-II में लंबित था और उसे एसीएम जयपुर शहर-I, जयपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां विषयगत भूमि के स्थल और रिकार्ड के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 17 अगस्त, 2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया था।

(ज) 12 जून, 2015 को मामला कैंप कोर्ट भपुरा में राजस्व लोक अदालत के समक्ष उठाया गया था और विभिन्न पक्षों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे और न्यायालय ने आपत्तियों (कुरेजत रिपोर्ट) पर विचार करने के बाद एक आदेश पारित किया कि तहसीलदार से प्राप्त आपत्तियों (कुरेजत रिपोर्ट) के बाद, मुकदमे की संपत्ति का विभाजन किया गया और अलग निर्णय और डिक्री तैयार की जानी थी।

(झ) 12 जून, 2015 का निर्णय और डिक्री पूरी तरह से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई थी और निर्णय में, श्रीमती द्वारा दायर मुकदमे में मामले की लंबितता के संबंध में एक नोट संलग्न किया गया था। भंवरलाल (रिट याचिका में वर्तमान याचिकाकर्ता) के खिलाफ कृष्णा देवी और उक्त मुकदमे में 17 अगस्त, 2004 को अंतरिम आदेश पारित किया गया।

(ञ) 12 जून, 2015 का निर्णय और डिक्री याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में पारित की गई थी और याचिकाकर्ता ने किसी समझौते/निपटान पर हस्ताक्षर करना या कोई डिक्री पारित करने के लिए कोई सहमति देने पर कभी भी अपना पक्ष नहीं रखा था।

(ट) याचिकाकर्ता ने 12 जून, 2015 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

अपील दायर की, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से आपत्ति जताई कि तहसीलदार की रिपोर्ट मिलीभगत से तैयार की गई थी और कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्हें दी गई और उनकी अनुपस्थिति में 11 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर वादी के पक्ष में मुख्य अजमेर रोड से सटी जमीन देकर मनमाने ढंग से जमीन का बंटवारा कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उनके और श्रीमती कृष्णा देवी के बीच एक मुकदमे के लंबित होने पर भी आपत्ति जताई थी और उक्त वाद के लंबित होने के बावजूद अंतिम डिक्री पारित कर दी गई।

(ठ) प्रत्यर्थी-श्रीमती कृष्णा देवी ने 12 जून, 2015 की प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील दायर की थी और राजस्व अपीलीय प्राधिकरण ने 15 जुलाई, 2015 के आदेश के तहत इसकी अनुमति दी थी।

(ड) उक्त आदेश की समीक्षा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2015 द्वारा की गई और दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आदेश को वापस ले लिया गया।

(ढ) श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा दायर अपील संख्या 545/2015/223 के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील संख्या 336/2015/223 को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने सामान्य आदेश दिनांक 1 फरवरी, 2016 द्वारा अपास्त कर दिया। अपील और 12 जून, 2015 के निर्णय और डिक्री दोनों को बरकरार रखा गया।

(ण) राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित 1 फरवरी, 2016 के आदेश को प्रत्यर्थी - श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा चुनौती नहीं दी गई।

(त) प्रत्यर्थी - श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता भंवरलाल के खिलाफ दायर मुकदमा अभी भी उसी न्यायालय, अर्थात एसीएम जयपुर सिटी-I, जयपुर में लंबित है और कब्जे और रिकॉर्ड के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2004 अभी भी जारी है।

(थ) 12 जून 2015 को वाद के पक्षकार को उपस्थित नहीं किया गया और उनके अधिवक्ता द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर राजस्व लोक अदालत में अंतिम निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 12 जून 2015 को पारित कर दिया दी गई।

(द) याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता श्री खुर्शीद अहमद के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने वादी के साथ मिलीभगत कर काम किया है।

(ध) याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कथित कदाचार के लिए आपराधिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन वैशाली नगर, जयपुर में एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सहमति डिक्री या राजस्व लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता के बारे में मुद्दे पर पहले निर्णय लेने की आवश्यकता है।

इस न्यायालय ने पाया कि 12 जून, 2015 का निर्णय और डिक्री एसीएम जयपुर शहर- I, जयपुर द्वारा राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया था और मुकदमे की सुनवाई नियमित अदालत में नहीं हुई है।

इस मामले के तथ्यों से यह न्यायालय पाता है कि किसी भी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया है कि राजस्व लोक अदालत के पास लोक अदालत में मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए एक पक्ष के पास उपलब्ध उपाय के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने *पंजाब सरकार और अन्य बनाम जालौर सिंह एवं अन्य (सुप्रा.),* के मामले में विचार किया है। जिससे यह माना जाता है कि जहां पक्षकारों के बीच समझौते के संदर्भ में लोक अदालत द्वारा कोई पंचाट दिया जाता है, तो वह अंतिम हो जाता है और समझौते के पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है और निष्पादन योग्य हो जाता है जैसे कि यह एक डिक्री है एक सिविल कोर्ट और यदि कोई पक्ष समझौते के आधार पर ऐसे निर्णय को चुनौती देना चाहता है, तो यह केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और/या अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका दायर करके किया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा संख्या 12 तत्काल

संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया गया है:

> "12. यह सच है कि जहां पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर लोक अदालत द्वारा कोई पंचाट दिया जाता है, (जो पक्षकारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होता है और लोक अदालत के निर्णय के साथ संलग्न होता है), तो यह अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी हो जाता है। समझौता इस प्रकार निष्पादन योग्य हो जाता है जैसे कि यह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो, और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। यदि कोई पक्ष समझौते के आधार पर ऐसे निर्णय को चुनौती देना चाहता है, तो यह केवल संविधान के अनुच्छेद 226 और/या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर करके किया जा सकता है, वह भी बहुत सीमित आधार पर। लेकिन जहां पक्षकारों द्वारा किसी समझौते या समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं और लोक अदालत का आदेश किसी समझौते का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन प्रत्यर्थी को निर्देश देता है कि यदि वह आदेश से सहमत है तो भुगतान करे, या इसके लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए।
>
> अपील का गुणागुण के आधार पर निपटान, यदि वह सहमत नहीं है, लोक अदालत का पंचाट नहीं है। ऐसे आदेश को अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में चुनौती देने का प्रश्न नहीं उठता। जैसाकि पहले ही देखा जा चुका है, ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को अपील को सुनना चाहिए और गुणागुण के आधार पर उसका निपटारा करना चाहिए था।"

उच्चतम न्यायालय ने संपदा अधिकारी बनाम कर्नल एच. वी. मनकोटिया (सेवानिवृत्त) [2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 898] साथ ही भार्गवी कंस्ट्रक्शन और अन्य बनाम कोथाकापु मुथ्यम एवं अन्य [(2018) 13 एससीसी 480] के हालिया मामले में इस सिद्धांत को दोहराया है कि यदि पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है, तो लोक अदालत को योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

तदनुसार, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए सही ढंग से दायर की गई है।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई स्थिरता की पूर्व आपत्ति पर भी विचार किया और तदनुसार, 20 अप्रैल, 2022 को, इस न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, याचिकाकर्ता को रिट याचिका के माध्यम से लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायत पर अपने अधिकारों के लिए चुनौती देने का अधिकार है और इस प्रकार, इस न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर मामले की जांच करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, रिट याचिका की पोषणीयता के बारे में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति अपास्त कर दी गई है और याचिकाकर्ता ने सही तरीके से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा अब राजस्व लोक अदालत में निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की वैधता के संबंध में है।

इस न्यायालय ने पाया कि विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमे का निर्णय मुकदमे में विभिन्न प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के संदर्भ में किया गया था, जिसमें उन्होंने संपत्ति के विभाजन और प्रत्येक सह-हिस्सेदार को निर्धारित हिस्सा आवंटित करने और तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने की बात स्वीकार की थी। याचिकाकर्ता और अन्य प्रत्यर्थी अपने लिखित बयान के अनुसार भूमि के विभाजन के लिए सहमत हुए। निचली अदालत द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री में, तहसीलदार के माध्यम से आपत्तियों की आवश्यकता थी और तहसीलदार ने रिपोर्ट (कुरेजत रिपोर्ट) तैयार की और याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया और उचित पक्षों की अनुपस्थिति में, तहसीलदार ने रिपोर्ट (कुरेजत रिपोर्ट) तैयार की और इसे निचली अदालत में निर्धारित अगली तारीख से पहले जमा कर दें।

इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व लोक अदालत, जिसने आदेश पारित किया, में पक्षकारों की उपस्थिति नहीं थी और उनकी अनुपस्थिति में निर्णय और डिक्री पारित कर

दी गई।

इस न्यायालय ने पाया कि 2009 के विनियम लोक अदालत में प्रक्रिया प्रदान करते हैं और इसके अलावा, एक पंचाट कैसे निकाला जाना है। 2009 के विनियमों की प्रासंगिक विनियम संख्या 17 यहां तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत की गई है :

"17. पंचाट - (1) लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के तहत पक्षकारों द्वारा सहमत निपटान या समझौते की शर्तों को शामिल करके पंचाट तैयार करना केवल एक प्रशासनिक कार्य है।

(2) जब दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं या अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं और लोक अदालत के सदस्य उस पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं, तो यह एक पंचाट बन जाता है। (परिशिष्ट-I में एक नमूना देखें) लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट विस्तृत और स्पष्ट होगा और स्थानीय अदालतों में इस्तेमाल होने वाली क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी में लिखा जाएगा। इसमें मामले का विवरण, केस संख्या, अदालत का नाम और पक्षकारों के नाम, प्राप्ति की तारीख, रजिस्टर स्थायी रजिस्टर में मामले को निर्दिष्ट संख्या (विनियम-20 के तहत प्रदान किए गए अनुसार बनाए रखा गया) और निपटान की तारीख उल्लिखित की जाएगी। जहां भी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, उन्हें लोक अदालत के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करने से पहले समझौते या पंचाट पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होनी चाहिए।

(3) किसी न्यायालय से लोक अदालत को संदर्भित मामलों में, पंचाट में यह उल्लेख किया जाएगा कि वादी या याचिकाकर्ता प्रेषित अदालत शुल्क की वापसी का पात्र है।

(4) जहां पक्षकारों के साथ अधिवक्ता नहीं हैं या उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोक अदालत के सदस्य निपटान दर्ज करने से पहले पक्षकारों की पहचान भी सत्यापित करेंगे।

(5) लोक अदालत के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षकार समझौता की शर्तों को पूरी तरह समझने और दर्ज करने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। लोक अदालत के सदस्यों को अपने हस्ताक्षर करने से पहले निम्नलिखित के बारे में भी संतुष्ट होना होगा:

(क) कि निपटान की शर्तें अनुचित या अवैध या एकतरफा नहीं हैं; और

(ख) कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, किसी धमकी, दबाव या अनुचित प्रभाव के कारण नहीं।

(6) लोक अदालत के सदस्यों को अपने हस्ताक्षर केवल उनके समक्ष हुए समझौते पर ही करने चाहिए और लोक अदालत के बाहर किसी तीसरे पक्ष की सहायता से पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोक अदालतों का बेईमान पक्षकारों द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, आदि के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

(7) लोक अदालत आपसी सहमति से किसी को जमानत या तलाक नहीं देगी।

(8) मूल पंचाट न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा (मुकदमेबाजी पूर्व मामले में, मूल पंचाट संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति के पास रखा जा सकता है) 7/78 और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव या सचिव या, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उन्हें सही होने के लिए विधिवत प्रमाणित करते हुए प्रत्येक पक्ष को पंचाट की एक प्रति दी जाएगी। तालुक विधिक सेवा समितियों के अध्यक्ष निःशुल्क होंगे और सभी पुरस्कारों पर संबंधित प्राधिकरण या समिति की आधिकारिक मुहर लगाई जाएगी।

2009 के विनियमों के विनियम 17 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पक्षों द्वारा सहमत निपटान या समझौते की शर्तों को पंचाट के रूप में तैयार किया जाता है और दोनों पक्ष अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं और लोक अदालत के सदस्य इस पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं और फिर यह एक पंचाट बन जाता है। उक्त विनियमन में यह भी प्रावधान है कि जब भी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया जाता है, तो उन्हें लोक अदालत के सदस्यों के हस्ताक्षर करने से पहले समझौते और पंचाट पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। उक्त विनियम में प्रावधान है कि यदि पक्षकारों के साथ अधिवक्ता नहीं हैं या उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो लोक अदालत के सदस्य समझौता दर्ज करने से पहले पक्षकारों की पहचान का सत्यापन भी करेंगे।

इस न्यायालय ने पाया कि 2009 के विनियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, यदि लोक अदालत से पहले निपटान की कोई भी शर्त आनी थी, तो समझौते के आधार पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले पक्षकारों की उपस्थिति और उनके हस्ताक्षर आवश्यक थे। जैसाकि कथित तौर पर पक्षकारों के बीच हुआ था।

पंजाब सरकार और अन्य बनाम जालौर सिंह एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि लोक अदालतों का कोई न्यायिक या न्यायिक कार्य नहीं है और पंचाट देना एक मामला है। लोक अदालत की उपस्थिति में पक्षों द्वारा सहमत निपटान या समझौते की शर्तों को लोक अदालत के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक निष्पादन योग्य आदेश के रूप में शामिल करने का प्रशासनिक कार्य है। उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार समझौते पर पक्षों के हस्ताक्षर को भी आवश्यक माना गया है।

सेवा सिंह (सुप्रा.) के मामले में निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया, इस स्थिति को भी दोहराता है कि लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, यदि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं होता है और ऐसा समझौता होता है या मुकदमे के पक्षकारों की सहमति लेकर समझौता किया जाना चाहिए और लोक अदालत को पक्षकारों द्वारा दी गई सहमति की वास्तविकता के बारे में सत्यापित करना होगा।

सेवा सिंह (सुप्रा.) के मामले में न्यायालय ने आगे कहा है कि एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के उचित और विशिष्ट निर्देशों के बिना कोई समझौता या रियायत नहीं दे सकता है और इस प्रकार, पक्षकारों को अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है और उनके बयान दर्ज कराए जाएं और उसके बाद पंचाट पारित किया जाए।

इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में कानून की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसाकि माना जाता है। याचिकाकर्ता न्यायालय में मौजूद नहीं था और यहां तक कि उसे संपत्ति का बंटवारा और इस पर आपत्ति जताना मुकदमे में प्रत्येक पक्ष को कौन सा हिस्सा दिया जाना था पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के समय आपत्ति

उठाने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती कृष्णा देवी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय संबंधित न्यायालय के समक्ष कथित समझौते के बारे में अपनी शिकायत करना है और इस तरह, वह निर्णय पर निर्भर है। (श्रीमती) पुष्पा देवी भगत (मृत) एल.आर. साधना राय (सुप्रा.), के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, वह समझौते के संबंध में है, यदि यह किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत या किसी अन्य माध्यम से किया जाता है, इसे सिविल कोर्ट के समक्ष चुनौती देने की आवश्यकता है, जहां इस तरह के समझौते पर कार्रवाई की गई है।

यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता की दलील को स्वीकार करने से बचता है क्योंकि कानून का उक्त सिद्धांत उन आदेशों के संबंध में लागू नहीं होगा, जो लोक अदालत में पारित किए जाते हैं।

प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलील कि विवाद में प्रत्येक पक्ष के हिस्से के बारे में स्वीकारोक्ति है और याचिकाकर्ता ने वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बयान दायर किया है, उसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यह कहना पर्याप्त है कि वास्तविक विभाजन या संपत्ति का विशेष हिस्सा होना, एक विवाद था और यह सभी पक्षों द्वारा उनके हिस्से और कब्जे के संबंध में आपत्तियों पर विचार करके और भूमि के किस हिस्से पर, वे पात्र थे, संपत्ति के एक विशेष हिस्से या विभाजन के असाइनमेंट के संबंध में था।

एक बार याचिकाकर्ता को इस बात पर आपत्ति थी कि मुख्य सड़क से सटी जमीन का कुछ महत्वपूर्ण टुकड़ा वादी के हिस्से में देकर तहसीलदार द्वारा मनमाने और मिलीभगत से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो ऐसी पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया या प्रारंभिक डिक्री तैयार करते समय, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के उचित विभाजन और विभाजन के बारे में अंतिम निर्णय और डिक्री पारित करते समय आपत्ति उठाने से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता के पास समझौते/निपटान पर हस्ताक्षर करने की पूरी क्षमता थी और ऐसी प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, इस न्यायालय का मानना है कि यदि कोई समझौता होना था लोक अदालत के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक थी और उनकी अनुपस्थिति में कोई समझौता/निपटारा नहीं हो सकता था।

इस न्यायालय ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उसकी ओर से रियायत देने की अपनी शक्तियों से परे काम किया और इस तरह, मामले की सूचना बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ-साथ पुलिस प्राधिकारी को भी दी गई।

इस न्यायालय ने पाया कि राजस्व अपीलीय प्राधिकरण और राजस्व बोर्ड भी सभी तथ्यात्मक और विधिक पहलुओं को ध्यान में रखने में विफल रहे और उन्होंने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा है। लोक अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील को सुनवाई योग्य नहीं मानने के अलावा, राजस्व बोर्ड ने मामले की योग्यता के आधार पर निष्कर्ष भी दिए हैं और इस प्रकार, राजस्व अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ राजस्व बोर्ड ने भी विवाद की सही ढंग से सराहना नहीं की है।

यह न्यायालय यह देखने के लिए भी बाध्य है कि राजस्व अधिकारियों ने मामलों का निर्णय करते समय मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी नजरअंदाज कर दिया और वर्तमान मामला इस तरह के गलत कार्य का एक ज्वलंत उदाहरण है। निचली अदालत-एसीएम, जयपुर शहर-I, जयपुर, जिसने अंतिम निर्णय और डिक्री पारित की है, को एक मामले से अवगत कराया गया था, जो उन्हीं पक्षों, अर्थात श्रीमती के बीच लंबित है। कृष्णा देवी और भंवरलाल (रिट में याचिकाकर्ता याचिका), जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया गया। कब्जे और राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में मामला जारी है और अभी अंतिम निर्णय और डिक्री पारित की गई है।

जिस तरह से लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किए बिना तारीख से पहले मामले की सुनवाई की गई और निर्णय और डिक्री पारित की गई। यह

देखने के लिए पर्याप्त सतर्क रहे कि विवाद, जो पक्षकारों, अर्थात प्रत्यर्थी और याचिकाकर्ता के बीच हल नहीं हुआ था, उनके अधिकारों के अंतिम निर्धारण में परिणत नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने 12 जून, 2015 को अंतिम निर्णय और डिक्री पारित कर दी।

इस न्यायालय ने पाया कि 12 जून, 2015 के अंतिम निर्णय और डिक्री को अपास्त करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, 12 जून, 2015 के अंतिम निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है। राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2019 एवं राजस्व अपीलीय प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01 फरवरी 2016 को भी अपास्त किया जाता है।

यह न्यायालय 2 जून, 2015 के प्रारंभिक निर्णय और डिक्री को बरकरार रखता है, क्योंकि यह प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता और अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर लिखित बयान के आधार पर पारित किया गया था और न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

तदनुसार, रिट याचिका उस सीमा तक स्वीकार्य है। पुरालेख, रिट याचिका उस सीमा तक है।

(अशोक कुमार गौर), न्यायमूर्ति

Preeti Asopa /15

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।